दर्ज किया गया कि इतनी अधिक संख्या को बुलाना सही नहीं था। इसलिए, तत्काल मामले में प्रार्थी को साबित करना था कि बोर्ड द्वारा किया गया अंकन स्पष्ट रूप से अनियमित था या विकृत उद्देश्यों से प्रभावित था। यही केवल तब माना जा सकता है जब अनुमान अनियमित हो या अनियमितता का जोखिम इतना उच्च हो कि कोई सामान्य व्यक्ति अनियमितता को अवश्य मानेगा। लेकिन फिर भी प्रार्थी ने अपनी मामले को समर्थन में कोई सामग्री उपलब्ध नहीं कराई है या कोई संदेश प्रस्तुत नहीं किया है। इस प्रकार, मामले के इस दृष्टिकोण में, प्रार्थी के वकील का दावा, पूर्व में उल्लिखित, त्यागने के योग्य है।

(19) कोई और सवाल विचार के लिए उत्पन्न नहीं होता।

(20) ऊपर दर्ज किए गए कारणों के आधार पर, यह रिट पिटीशन बिना किसी मूल्य के हैं, विफल हैं और खारिज किए जाते हैं। मामले की परिस्थितियों में, हम भविष्य में कोई भी निर्णय नहीं करते।

पूर्ण बेंच

पी. सी. जैन, मुख्य न्यायाधीश, एस. पी. गोयल और एस. एस. कांग, न्यायाधीश

राकेश कुमार और अन्य,—अपीलकर्ता,

बनाम

सत पाल,—प्रतिद्वंद्वी

नियमित दूसरी अपील संख्या 1203/1985

14 अप्रैल, 1986

विशेष प्रत्यारोपण अधिनियम (1963 का अधिनियम)—धारा 12(3)—बिक्री के लिए समझौता—विशेष प्रत्यारोपण— क्या उस से बातचीत में बातचीत के लिए कम भाग के लिए हो सकता है

निर्णय, कि विशेष नियमन का योग्यता, उस भाग का यदि भाग किया जाना होता है, जिसे छोड़ा जाना चाहिए, तो वह पूरे में से एक बड़ा हिस्सा बनता है, हालांकि धन में मुआवजा की अनुमति देने वाली, या यदि छोड़ा जाना चाहिए भाग धन में मुआवजा देने के लिए संभव नहीं है। हालांकि, दूसरी पार्टी की मामले में, अदालत इस प्रकार के किसी भी पक्ष पर निर्देश दे सकती है, जो डिफॉल्ट में है, ताकि वह विशेष रूप से उसके हिस्से का इतना हिस्सा कर सके जितना कि वह कर सकता है यदि मामले का पक्ष उन शर्तों को पूरा करता है जिन्हें उस धारा की सूचीबद्ध प्रावधानों में उल्लिखित किया गया है। इस प्रावधान के द्वारा, यह कहा नहीं जा सकता कि एक डिक्री विशेष प्रत्यारोपण के लिए आदेश नहीं दिया जा सकता है उस प्रॉपर्टी के कम हिस्से के लिए जो बेचने के लिए सहमत किया

गया हो। अधिनियम की धारा 12 ने संधि की अनुमति दी है कि अवधारणा के लिए कि एक कर्ता ने वहाँ सहभागितारता है, जिसमें कुछ अन्य व्यक्तियों को भी हिस्सा है, तो उस प्रॉपर्टी के लिए धारा 12(3) के तहत विशेष प्रत्यारोपण का आदेश दिया जा सकता है उसके हिस्से के संदर्भ में। अन्य शब्दों में, उसको इस बारीकी के लिए दिशा दी जा सकती है कि प्लेंटिफ ने सभी दावे को छोड़ दिया होता है और यह भी कि वह डिफॉल्ट के माध्यम से हुई कमी या हानि या नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति के सभी अधिकारों को त्यागता है। इसलिए, यह निर्णय किया गया है कि विशेष प्रत्यारोपण का आदेश दिया जा सकता है कि बेचने के लिए सहमत किया गया हो उस प्रॉपर्टी के कम हिस्से के लिए, यहाँ तक कि उस अधिनियम की धारा 12 में उल्लिखित प्रावधानों के पूरा होने की शर्त से।

(निर्णय 9 और 11)

(माननीय एकल न्यायाधीश श्री एस. पी. गोयल ने इस मामले में शामिल एक महत्त्वपूर्ण कानूनी सवाल के निर्णय के लिए एक बड़ी बेंच को संदर्भित किया जो दिनांक 23 मई, 1985 को हुआ था। उन्होंने मुख्य न्यायाधीश श्री पी. सी. जैन और माननीय न्यायाधीश श्री सुखदेव सिंह कांग के एक और बड़ी बेंच को संदर्भित किया। 13 फरवरी, 1986 को। उन्होंने महत्त्वपूर्ण कानूनी सवाल के निर्णय के बाद फिर से मामले को शिक्षित एकल न्यायाधीश के पास सूचीबद्ध करने के लिए संदर्भित किया था।

निर्णय

प्रेम चंद जैन, सी.जे

1. जिस कानूनी प्रश्न पर हमें निर्णय लेने की आवश्यकता है, उसे इस प्रकार तैयार किया जा सकता है:--

"क्या संपत्ति के बेचने पर सहमति से कम हिस्सेदारी के लिए विशिष्ट प्रदर्शन के लिए डिक्री का आदेश दिया जा सकता है?"

2. विवाद की सराहना करने के लिए, मामले की कुछ मुख्य विशेषताओं पर ध्यान दिया जा सकता है।

3. शिव राम सतपाल वादी और प्रतिवादी क्रमांक 1 से 3 तक के पिता थे। प्रतिवादी नंबर 4 रतन देवी, शिव राम की विधवा हैं। श्रीमती राज कुमारी और श्रीमती. वीणा शिवराम की पुत्रियाँ हैं। विवादित मकान मृतक शिवराम का था। राकेश कुमार और अन्य, प्रतिवादी, ने वादी का प्रतिनिधित्व किया कि श्रीमती। राज कुमारी और श्रीमती. वीना ने मुकदमे के पक्षों के पक्ष में विवाद में घर में अपने अधिकारों और शीर्षक को त्याग दिया था, जिसके

परिणामस्वरूप उनमें से प्रत्येक के पास विवाद में घर में 1/5 हिस्सा था। यह भी कहा गया है कि प्रतिवादियों ने वादी के साथ घर में अपना 4/5वां हिस्सा बेचने के लिए 12 जुलाई, 1980 को एक समझौता किया था। प्रतिवादियों को वादी से रु. बिक्री प्रतिफल में से 5,400/- और शेष राशि का भुगतान किश्तों में किया जाना था अर्थात रु. 30 अगस्त, 1980 को 9,000/- रु. 30 अक्टूबर, 1980 को 8,000/- रु. 30 दिसंबर, 1980 को 8,000/- रु.

यह आगे कहा गया है कि वादी ने प्रतिवादियों को रुपये का भुगतान किया। 30 अगस्त, 1980 को 9,000/-। 30 अक्टूबर, 1980 को, उन्होंने रुपये की राशि की पेशकश की। रसीद के विरुद्ध बिक्री प्रतिफल में से 8,000/-, लेकिन प्रतिवादियों ने उस राशि को स्वीकार करने से परहेज किया। 4 नवंबर, 1980 को एक नोटिस भी जारी किया गया था, लेकिन प्रतिवादियों ने उस नोटिस को स्वीकार नहीं किया; बल्कि उन्होंने वादी बनने के लिए एक नोटिस भेजा कि वह 30 अक्टूबर, 1980 को देय किश्तों का भुगतान करने में विफल रहे हैं, और उनके द्वारा भुगतान की गई राशि जब्त कर ली गई है। इसके बाद वादी ने प्रतिवादियों को पंजीकृत नोटिस भेजे। नतीजतन, वादी ने रुपये के शेष बिक्री विचार के भुगतान पर विवाद में घर में प्रतिवादियों के 4/5 वें हिस्से के संबंध में 12 जुलाई, 1980 के समझौते के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए मुकदमा दायर किया। 16,000/-.

4. प्रतिवादियों द्वारा मुकदमा लड़ा गया। प्रारंभिक आपत्तियाँ इस आशय की थीं कि घर बेचने के समझौते के विशिष्ट निष्पादन के लिए मुकदमा चलने योग्य नहीं था, यह मुकदमा आवश्यक पक्षों के गैर–जुड़ने के लिए बुरा था और बेचने का समझौता कानूनी रूप से लागू करने योग्य नहीं था। योग्यता के आधार पर, 12 जुलाई, 1980 को बिक्री के समझौते का निष्पादन विवादित नहीं था, न ही इस बात से इनकार किया गया था कि प्रतिवादियों को रुपये की राशि प्राप्त हुई थी। 5,400/- बयाना राशि और पहली किस्त रु. 8,000/- का भुगतान 30 अगस्त, 1980 को किया गया था। हालाँकि, इस बात से इनकार किया गया कि वादी ने कभी रुपये की किस्त की राशि प्राप्त करने के लिए प्रतिवादियों से संपर्क किया था। 30 अक्टूबर 1980 को 8,000/- बिक्री मूल्य से। इस तरीके से प्रतिवादियों ने 12 जुलाई, 1980 के समझौते के विशिष्ट निष्पादन के लिए वादी के दावे को खारिज कर दिया है।

5. पक्षों की दलीलों पर, ट्रायल कोर्ट द्वारा विभिन्न मुद्दे तय किए गए। पूरे मामले पर विचार करने पर, विद्वान अधीनस्थ न्यायाधीश प्रथम श्रेणी ने 18 मई, 1984 को अपने फैसले और डिक्री द्वारा, विशिष्ट प्रदर्शन के लिए डिक्री नहीं दी और इसके बजाय रुपये की वसूली के लिए डिक्री दी। 14,000/- और डिक्री की तारीख से वसूली तक वादी के पक्ष में और प्रतिवादी के विरुद्ध आनुपातिक लागत के साथ 6 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज। ट्रायल कोर्ट के फैसले और डिक्री से व्यथित महसूस करते हुए, वादी ने अपील दायर की। विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने अपील को स्वीकार कर लिया और राकेश कुमार और अन्य, प्रतिवादियों के खिलाफ रुपये की राशि के भुगतान पर विवाद में घर में 4/7 वें हिस्से के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए डिक्री प्रदान की। वादी द्वारा उन्हें 30,400/- रुपये घटाकर।

बयाना राशि के रूप में 14,400/- का भुगतान पहले ही किया जा चुका है। प्रतिवादियों द्वारा दायर की गई प्रति–आपत्तियाँ खारिज कर दी गईं।

6. विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के फैसले और डिक्री से असंतुष्ट, राकेश कुमार और अन्य प्रतिवादियों ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी, जो इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष सुनवाई के लिए आई थी। उठाए गए कानूनी मुद्दे के आलोक में पूरे मामले पर विचार करने पर, मेरे विद्वान भाई एसपी गोयल, जे. ने अपने आदेश दिनांक 23 मई, 1985 द्वारा, जो निम्नानुसार है, मामले को एक बड़ी पीठ द्वारा निर्णय के लिए भेजा गया:

" हरजिंदर सिंह बनाम करतार सिंह , 1975 रेव एलआर 377, इस न्यायालय के एक डीबी निर्णय पर भरोसा करते हुए, विद्वान वकील का तर्क है कि बिक्री के लिए सहमति से घर के कम हिस्से के लिए विशिष्ट प्रदर्शन के लिए डिक्री का आदेश नहीं दिया जा सकता है। यह निर्णय बालमुकंद बनाम कमला वती , एआईआर 1964 एससी 1385 (पैरा 11) में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित नियम के विपरीत है । बेंच द्वारा सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ध्यान नहीं दिया गया। फिर भी, यह उचित नहीं होगा मैं अकेले बैठकर इसके विपरीत विचार रख रहा हूं। फलस्वरूप इस अपील को स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि इसे मेरे भगवान, मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा जाए ताकि ऊपर उल्लिखित प्रश्न को निपटाने के लिए एक बड़ी पीठ का गठन किया जा सके।

संदर्भ पर, मामले को इस न्यायालय की एक डिवीजन बेंच के समक्ष रखा गया था, जो एसपी गोयल, जे. के दृष्टिकोण से सहमत था और पाया कि हरजिंदर सिंह बनाम करतार सिंह , 1975 रेव एलआर 377 में लिया गया दृष्टिकोण पुनर्विचार के योग्य था। मामले को अभी भी बड़ी बेंच द्वारा तय करने के लिए भेजा गया है। इस तरह हम मामले को समझ गए हैं।

7. जैसा कि निर्णय के प्रारंभिक भाग में आया है, एकमात्र बिंदु और कानून का प्रश्न जिस पर निर्धारण की आवश्यकता है, वह यह है कि क्या घर को बेचने पर सहमति से कम हिस्सेदारी के लिए विशिष्ट प्रदर्शन के लिए डिक्री का आदेश नहीं दिया जा सकता है।

8. पक्षों के विद्वान वकील को सुनने के बाद, हमारा विचार है कि उपरोक्त प्रश्न का उत्तर सकारात्मक होना चाहिए।

9. विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 12 अनुबंध के हिस्से के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए प्रावधान करती है और जिस प्रासंगिक प्रावधान से हम चिंतित हैं, वह निम्नलिखित शर्तों में है:--

"12. अनुबंध के भाग का विशिष्ट प्रदर्शन (1) और (2) xxxx (3) जहां अनुबंध का एक पक्ष अपने हिस्से का पूरा प्रदर्शन करने में असमर्थ है, और जो हिस्सा अधूरा छोड़ दिया जाना चाहिए:--

(ए) पैसे में मुआवजे की बात स्वीकार करते हुए, पूरे का एक बड़ा हिस्सा बनता है; या

(बी) पैसे में मुआवजा स्वीकार नहीं करता; वह विशिष्ट पालन के लिए डिक्री प्राप्त करने का हकदार नहीं है, लेकिन न्यायालय, दूसरे पक्ष के मुकदमे में, डिफ़ॉल्ट पक्ष को अनुबंध के अपने हिस्से का उतना ही विशेष रूप से पालन करने का निर्देश दे सकता है जितना वह कर सकता है, यदि दूसरा पक्ष– –

(i) खंड (ए) के अंतर्गत आने वाले मामले में, पूरे अनुबंध के लिए सहमत प्रतिफल का भुगतान करता है या भुगतान कर चुका है, उस हिस्से के लिए प्रतिफल को घटाकर जिसे निष्पादित नहीं किया जाना चाहिए और खंड (बी) के अंतर्गत आने वाले मामले में, भुगतान करता है, या बिना किसी कटौती के संपूर्ण अनुबंध के लिए प्रतिफल का भुगतान कर दिया है; और

(ii) किसी भी मामले में, अनुबंध के शेष भाग के प्रदर्शन के सभी दावों और मुआवजे के सभी अधिकार, या तो कमी के लिए या प्रतिवादी की डिफ़ॉल्ट के माध्यम से उसे हुई हानि या क्षति के लिए त्याग देता है।

(4) XXXXX 1963 के अधिनियम के लागू होने से पहले, 1877 के अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधान, धारा 12(3) के अनुरूप, धारा 15 थे , जो इस प्रकार है:––

"अनुबंध के उस हिस्से का विशिष्ट निष्पादन जहां अधूरा हिस्सा बड़ा है।

15. जहां किसी अनुबंध का कोई पक्ष अपने पूरे हिस्से का पालन करने में असमर्थ है, और जिस हिस्से को पूरा नहीं किया जाना चाहिए वह पूरे का एक बड़ा हिस्सा बनता है, या पैसे में मुआवजा स्वीकार नहीं करता है, तो वह प्राप्त करने का हकदार नहीं है विशिष्ट निष्पादन के लिए एक आदेश. लेकिन न्यायालय दूसरे पक्ष के मुकदमे में, डिफ़ॉल्ट पक्ष को निर्देश दे सकता है कि वह अनुबंध के अपने हिस्से का उतना ही विशेष रूप से पालन करे जितना वह कर सकता है, बशर्ते कि वादी आगे के निष्पादन के लिए सभी दावे और मुआवजे के सभी अधिकार त्याग दे। कमी के लिए या प्रतिवादी की चूक के कारण उसे हुई हानि या क्षति के लिए।"

10. विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 की धारा 12 की उपधारा (3) में यह प्रावधान है कि जहां किसी अनुबंध का कोई पक्ष अपने पूरे हिस्से को निष्पादित करने में असमर्थ है, तो वह विशिष्ट राहत के लिए डिक्री प्राप्त करने का हकदार नहीं है। निष्पादन यदि वह भाग जिसे बिना निष्पादित छोड़ दिया जाना चाहिए वह संपूर्ण का एक बड़ा हिस्सा बनता है, हालांकि पैसे में मुआवजे को स्वीकार करना, या यदि वह हिस्सा जिसे बिना निष्पादित किए छोड़ दिया जाना चाहिए वह पैसे में मुआवजे को स्वीकार नहीं करता है। हालाँकि, दूसरे पक्ष के मुकदमे में, न्यायालय ऐसे डिफ़ॉल्ट पक्ष को निर्देश दे सकता है कि वह अनुबंध के अपने हिस्से का उतना ही विशेष रूप से पालन करे जितना वह कर सकता है यदि मुकदमा लाने वाला पक्ष यानी वादी सीएलएस में निर्धारित शर्तों को पूरा करता है। . (i)

और (ii) उस उपधारा के। ये शर्तें हैं: सबसे पहले, उस मामले में जिसमें जिस हिस्से को निष्पादित नहीं किया जाना चाहिए, वह पूरे का एक बड़ा हिस्सा बनता है और पैसे में मुआवजे की अनुमति देता है, वादी को पूरे अनुबंध के लिए सहमत विचार का भुगतान करना होगा, जो कि प्रतिफल से कम है। जिस हिस्से को निष्पादित नहीं किया जाना चाहिए, उसे छोड़ दिया जाना चाहिए, जबकि ऐसे मामले में जहां गैर-निष्पादित हिस्से को पैसे में मुआवजे की अनुमति नहीं है, वादी को बिना किसी कटौती के पूरे अनुबंध के लिए प्रतिफल का भुगतान करना होगा। दूसरी शर्त यह है कि उपरोक्त दो मामलों में से किसी एक में वादी को अनुबंध के शेष भाग के निष्पादन के सभी दावों और मुआवजे के सभी अधिकार, या तो कमी के लिए या डिफ़ॉल्ट के माध्यम से उसे हुई हानि या क्षति के लिए त्यागना होगा। प्रतिवादी का.

जैसा कि पहले देखा गया था, पुराने अधिनियम की धारा 15 के तहत भी यही स्थिति थी । इस प्रावधान को ध्यान में रखते हुए, शायद ही यह आग्रह किया जा सकता है कि संपत्ति के बेचने पर सहमति से कम हिस्सेदारी के लिए विशिष्ट प्रदर्शन के लिए डिक्री का आदेश नहीं दिया जा सकता है। अधिनियम की धारा 12 धारा के संबंधित प्रावधानों में उल्लिखित पूर्व-आवश्यकताओं की संतुष्टि की स्थिति में अनुबंध के एक हिस्से के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए डिक्री पारित करने की परिकल्पना करती है। जहां कोई पार्टी किसी संपत्ति को बेचने के लिए सहमत होती है जिसमें कुछ अन्य व्यक्तियों का भी हिस्सा होता है, तो ऐसी संपत्ति के संबंध में धारा 12(3) के तहत अनुबंध के उनके हिस्से के इतने हिस्से के संबंध में विशिष्ट प्रदर्शन को निर्देशित किया जा सकता है जैसा कि वह/वे प्रदर्शन कर सकते थे। दूसरे शब्दों में, उन्हें वादी को अपने हिस्से की जमीन बेचने का निर्देश दिया जा सकता है, लेकिन ऐसा तब किया जा सकता है, जब वादी आगे के प्रदर्शन के लिए सभी दावों को त्याग दे और साथ ही कमी या हानि के लिए मुआवजे का पूरा अधिकार भी छोड़ दे। प्रतिवादी की चूक से हुई क्षति। मुद्दा पूर्ण नहीं है जैसा कि बालमुकंद बनाम कमला वती , एआईआर 1964 एससी 1385 में, उनके आधिपत्य द्वारा यह देखा गया है कि वादी विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 15 के लाभ का हकदार होगा और इसके लिए एक डिक्री होगी एक हिस्सा हमेशा दिया जा सकता है; लेकिन इसे अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि उस मामले में वादी डिक्री प्राप्त करने के लिए संपूर्ण प्रतिफल का भुगतान करने को तैयार नहीं था।

11. हरिंदर सिंह के मामले (1975 रेव एलआर 377) (सुप्रा) में इस न्यायालय के फैसले पर आते हुए, जिसके लिए संदर्भ की आवश्यकता थी, मुझे लगता है कि उक्त फैसले का यह अर्थ नहीं लगाया जा सकता है कि एस के तहत विशिष्ट प्रदर्शन के लिए कोई डिक्री नहीं दी जा सकती है । 1963 के अधिनियम के 12 प्रतिवादी के हिस्से के लिए जो पूरी संपत्ति बेचने के लिए सहमत हो गया था। उस मामले में, तथ्यों से निपटते समय, विद्वान न्यायाधीश इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि मामला अधिनियम की धारा 12 के तहत प्रदान किए गए किसी भी अपवाद के अंतर्गत नहीं आता है। ऐसा प्रतीत होता है कि उस मामले में विद्वान न्यायाधीशों के समक्ष कोई दलील नहीं दी गई थी कि प्रतिवादी के 1/2 हिस्से के लिए

डिक्री पारित की जाए क्योंकि वादी अनुबंध के शेष भाग के निष्पादन के सभी दावों और सभी अधिकारों को त्यागने के लिए तैयार था। क्षतिपूर्ति, या तो कमी के लिए या प्रतिवादी की चूक के कारण उसे हुई हानि या क्षति के लिए।

यह सही है कि विद्वान न्यायाधीशों ने आधे हिस्से की डिक्री देने से इनकार कर दिया, लेकिन, जैसा कि पहले देखा गया था। केवल 1/2 शेयर के लिए डिक्री का दावा करने वाले वादी द्वारा याचिका प्रस्तुत नहीं की गई थी, मेरे विचार में विद्वान न्यायाधीशों ने केवल हर्जाना की राशि देने और रुपये की राशि की वापसी का आदेश देने में उचित ठहराया था। 2,000/- जो बयाना राशि के रूप में भुगतान किया गया था। जोर देने के लिए, उस मामले में विद्वान एकल न्यायाधीश ने रुपये के भुगतान पर प्रतिवादी के हिस्से की डिक्री दी थी। 10,000/- जब संपत्ति रुपये की राशि में बेचने पर सहमति हुई थी। 20,000/-. यदि उस मामले में वादी अधिनियम की धारा 12(3) के प्रावधानों का लाभ लेना चाहता था , तो वह एक अतिरिक्त वचन के साथ पूरी राशि का भुगतान करने के लिए बाध्य था कि वह शेष भाग में किसी भी ब्याज का दावा नहीं करेगा। अनुबंध की कमी के लिए या प्रतिवादी की चूक के कारण उसे हुई हानि या क्षति के लिए मुआवजे का दावा भी नहीं करना चाहिए। मामले के इस दृष्टिकोण में, मुझे लगता है कि हरिंदर सिंह के मामले (1975 रेव एलआर 377) (सुप्रा) में निर्णय अलग-अलग है और उस मामले के तथ्यों पर सही निर्णय लिया गया है।

12. उपरोक्त चर्चा के परिणामस्वरूप, मेरा मानना है कि धारा 12 में उल्लिखित शर्तों की पूर्ति के अधीन संपत्ति को बेचने पर सहमति से कम हिस्सेदारी के लिए विशिष्ट प्रदर्शन के लिए डिक्री का आदेश दिया जा सकता है । मैं आगे आदेश देता हूं कि अपील अब गुण-दोष के आधार पर अन्य बिंदुओं पर निर्णय के लिए विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष वापस जाएगी।

13. तदनुसार उत्तर दिया गया।

अस्वीकरण :

स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

भुवनेश सैनी

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

नारनौल, हरियाणा